



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58487

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7866 वर्ष 2026

सुनील कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: कुलदीप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक **सुनील कुमार** की ओर से वाद अपराध संख्या 116/2025 में धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 117(2) और 89 के तहत बीएनएस, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, जिला इटावा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने घायल व्यक्तियों, अर्थात् रुचि, चेतना और नारायणी को गंभीर चोट पहुंचाई है।

4. आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और पक्षों के बीच पारिवारिक/वैवाहिक और दीवानी विवाद के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी-आवेदक और सूचनादाता परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि घायल रुचि के प्रारंभिक बयान में, उसने कहा है कि उसे गाय के कारण हुई दुर्घटना में चोट लगी है और बाद में जांच के दौरान, आरोपी-आवेदक सुनील कुमार की संलिप्तता का खुलासा पीड़ित/घायल रुचि के बाद के बयान (मजीफ बयान) में हुआ, जिसमें उसने कहा कि आरोपी-आवेदक ने घायल के पेट पर पैर मारकर उसे चोट पहुंचाई है। इस प्रकार, पीड़ित रुचि के प्रारंभिक बयान और बाद के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि किसी भी घायल व्यक्ति को कोई फ्रैक्चर या गंभीर चोट नहीं आई है। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल महिला का गर्भपात के कारण गर्भस्राव अचानक समाप्त हो गया, लेकिन आरोपी आवेदक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान, न तो एफआईआर में और न ही पीड़िता रुचि के प्रारंभिक बयान में, आरोपी आवेदक को कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका सौंपी गई है। इसके अलावा, आरोपी आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 05.02.2026 से जेल में है। इसके अलावा, विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि विचारपूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. इस बात पर विचार करने के बाद कि यद्यपि आरोपी-आवेदक, अर्थात् सुनील कुमार का नाम अन्य चार सह-आरोपियों के साथ एफआईआर में दर्ज है, यह स्वीकार किया जाता है कि शिकायतकर्ता/पीड़िता और आरोपी-आवेदक तथा एफआईआर में नामित अन्य सह-आरोपी आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं क्योंकि वे परिवार के सदस्य/रिश्तेदार हैं। एफआईआर और घायल रुचि के प्रारंभिक बयान में, रुचि के पेट पर गंभीर चोट पहुंचाने में आरोपी-आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है। रुचि ने अपने पेट पर चोट पहुंचाने के संबंध में अपनी भूमिका जांच के दौरान बहुत देर से, बाद के बयान (मजीद बयान) के आधार पर बताई है। विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में 06.02.2026 को पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 05.02.2026 से जेल में है। मुकदमे के निष्कर्ष को लेकर अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार क्षेत्र को देखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024 (एससी) मुकदमा 677) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद संख्या 53, संघ ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए। (2022) 10 एससीसी 51** और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को उसकी निजी मुचलके और दो जमानतों

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को समान राशि में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20 मार्च, 2026

के.एन

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”